

कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बंगलूरु में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सहि तोमर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 'समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान' की सोच के साथ कृषि के लिये अलग से बजट पेश किया गया, जिसमें कृषक कल्याण कोष की राशि 2 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपए की गई है।
- वर्ष 2021 से फसल बीमा पॉलिसीधारक कृषकों को 16 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किये गए।
- खरीफ 2021 से फसल बीमा पॉलिसियों वितरित करने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को इसका अनुसरण करने के निर्देश दिये हैं।
- कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा 'राज किसान साथी पोर्टल' बनाया गया है, जो किसानों एवं कृषि व्यवसायियों के लिये एकल खड़की के रूप में काम कर रहा है। इसमें कृषि से संबंधित सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सूचनाएँ, अनुदान सहायताएँ, लाइसेंस एवं पंजीयन आदि की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को हस्तांतरित किये गए हैं।
- 'राजस्थान जैविक खेती मशिन' के लिये कृषि बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। कृषि विपणन प्रसंस्करण व नरियात को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कार्यरत 120 कृषक उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य की सभी कृषि उपज मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 136 मंडी समितियों में ऑयल टेस्टिंग मशीन, ग्रेन फजिकिल एनालाइजर मशीन एवं वेईंग स्केल मशीन आदि उपकरणों की स्थापना की जा चुकी है।
- नेनो यूरिया (तरल) उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये जिलास्तरीय कार्यशालाएँ एवं किसान गोष्ठियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अब तक राज्य में 17 लाख नेनो यूरिया बॉटलस का वितरण किया जा चुका है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरा, ज्वार और अन्य छोटे मलिट्स के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये 'राजस्थान मलिट संवर्धन मशिन' शुरू किया गया है। इसको प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मलिट्स की स्थापना की जाएगी।
- जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2021-22 के दौरान 1 लाख किसानों को निःशुल्क जैव उर्वरक का वितरण किया गया। सरकार द्वारा डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में सगिल सुपर फास्फेट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में पहले जहाँ 50 लाख मीटरकि टन एस.एस.पी. का उपयोग होता था, वहीं इस वर्ष रिकॉर्ड 7.10 लाख मीटरकि टन एस.एस.पी. का वितरण हुआ।
- कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री कटारिया ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बैंकों द्वारा पोर्टल पर गलतियों के कारण पछिले वर्षों में 1 लाख 10 हजार प्रकरण केंद्र द्वारा गठित समिति को प्रेषित किये गए थे, जिनका शीघ्र नसितरण कर किसानों को राहत प्रदान की जाए।
- उन्होंने नेचुरल फार्मिंग एवं भारतीय पराकृतिक कृषि पद्धति योजना को शीघ्र लागू किये जाने का सुझाव भी दिया।
- उन्होंने राज्य में हो रही जैतून की खेती के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वसितृत अध्ययन एवं अनुसंधान तथा रबी के मौसम में राज्य में मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करने की आवश्यकता भी बताई।